"राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नीति" - पेट्रोलियम क्षेत्र पर हमला और प्रभाव

नोगेन चुटिया, महासचिव
पेट्रोलियम एंड गैस वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया

<u>एनएमपी एक स्थायी निजीकरण प्रक्रिया है :</u>

निजीकरण के सभी पिछले तरीकों पर काबू पाने और उन्हें दरकिनार करते हुए, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) एक स्थायी निजीकरण प्रक्रिया होने जा रही है, जिसके माध्यम से बिना किसी कैबिनेट निर्णय, संसद की मंजूरी या बजट में बदलाव की मंजूरी के बिना ही निजीकरण के लिए राष्ट्रीय संपत्ति को नियमित रूप से दे दिया जाएगा। यह और कुछ नहीं बल्कि मोदी सरकार की सार्वजनिक संपत्ति को अपने कॉरपोरेट साथियों को सौंपने का एक ज़बरदस्त प्रयास है और जाहिर तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के प्रेमियों के साथ-साथ सच्चे देश प्रेमियों के सामने एक बहुत ही गंभीर मामला है। यहां, हम **पेट्रोलियम क्षेत्र** में एनएमपी और भविष्य में इसके परिणामों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं।

<u>पेट्रोलियम क्षेत्र में एनएमपी:</u>

सरकार ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2022-2025 के दौरान, पेट्रोलियम क्षेत्र में मुद्रीकरण करने के लिए कुल 22,503 करोड़ रुपये की संपत्ति के बारे में सोचा जा रहा है।

निम्नलिखित सारांश है-

मुद्रीकरण के लिए विचार की गई संपत्ति: चरणबद्ध तरीके से (उत्पाद और एलपीजी पाइपलाइन) संख्या करोड़ रुपये में।

क्रमांक	संपत्ति प्रकार	वि. वर्ष 22	वि. वर्ष 23	वि. वर्ष 24	वि. वर्ष 25	कुल
1	पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	2,697	1,873	4,164	4,164	12,898
2	एलपीजी पाइपलाइन	0	40	183	183	405
3	हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र	600	600	-	-	1,200
4	इएसजी संपत्ति	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
	कुल	5,297	4,513	6,347	6,347	22,503

<u>मुद्रीकरण के लिए सूचीबद्ध संपत्तियां निम्नलिखित हैं:</u>

a) पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन।

b) एलपीजी पाइपलाइन

c) हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र।

d) ईएसजी संपत्ति (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सल्फर रिकवरी यूनिट, फ्लेयर गैस रिकवरी सिस्टम)।

<u>मुद्रीकरण के लिए पहचानी गई संपत्तियों के चरण:</u>

क्रमांक	संपत्ति प्रकार	वि. वर्ष 22	वि. वर्ष 23	वि. वर्ष 24	वि. वर्ष 25	कुल
1	पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन, किलो मीटर (कि.मी.)	755	629	906	906	3196
2	एलपीजी पाइपलाइन (कि.मी.)	-	141	296	296	733
3	हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र (संख्या)	1	1	-	-	2
4	इएसजी संपत्ति	-	-	-	-	-

<u>प्राकृतिक गैस पाइपलाइन:</u>

3930 कि.मी.	23%	22,503 करोड़ रुपये	4%
वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 25 तक मुद्रीकरण (कि.मी.)	वित्त वर्ष 22-25 में अधिक संपत्ति के आधार के प्रतिशत के रूप में संपत्ति मुद्रीकरण (%)	वित्त वर्ष 22-25 में मूल्य (रुपये करोड़)	मूल्य के संदर्भ में समग्र एनएमपी में हिस्सेदारी (%)

<u>पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन और अन्य संपत्तियां का मुद्रीकरण:</u>

3930 कि.मी.	23%	22,503 करोड़ रुपये	4%
वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 25 तक मुद्रीकरण (कि.मी.)	वित्त वर्ष 22-25 में अधिक संपत्ति के आधार के प्रतिशत के रूप में संपत्ति	वित्त वर्ष 22-25में मूल्य (रुपये करोड़)	मूल्य के संदर्भ में समग्र एनएमपी में हिस्सेदारी

	मुद्रीकरण (%)		(%)

मुद्रीकरण के लिए लक्षित परिसंपत्तियां:

a) गैस पाइपलाइन: 8154 कि.मी. (7928 कि.मी. मौजूदा पाइपलाइन और बाकी का निर्माण जारी है)।

b) वित्त वर्ष 22 के दौरान, 2229 कि.मी. लंबाई वाली दो पाइपलाइनों का मुद्रीकरण किया जाएगा।

- दाभोल-बेंगलुरू पाइपलाइन (1414 कि.मी. और 16 एमएमएससीएमडी क्षमता)
- दहेज-उरण-पनवेल-दाभोल पाइपलाइन (815 कि.मी. और 20 एमएमएससीएमडी क्षमता) (मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन)
- वित्त वर्ष 2013 के दौरान एचपीसीएल की मैंगलोर-हासन एलपीजी पाइपलाइन।

मुद्रीकरण कैसे किया जाएगा:

- पाइपलाइन नेटवर्क का मौजूदा क्षमता का उपयोग।
- संभावित मांग, विशेष रूप से जुड़े हुए क्षेत्रों पर आधारित।
- पाइपलाइन टैरिफ, उपयोग, अधिकतम उपयोग, रैंप अप आदि के आधार पर सांकेतिक मूल्य का अनुमान लगाना।
- मुद्रीकरण का दावा करने वाला औसत मूल्य 3.0 करोड़ रुपये प्रति पाइपलाइन किलोमीटर माना जा रहा है।

क्रमांक	नेटवर्क / क्षेत्र	लंबाई (कि.मी.)

1	हज़रा-विजयपुर-जगदीशपुर और गैस पुनर्वास और विस्तार परियोजना और दहेज़-विजयपुर पाइपलाइन नेटवर्क	5030
2	दहेज़-विजयपुर पाइपलाइन (ii) और विजयपुर-दादरी पाइपलाइन नेटवर्क	1290
3	त्रिपुरा नेटवर्क	60
4	कावेरी घाटी	242
5	छायंसा-झज्जर-हिसार पाइपलाइन नेटवर्क	304
6	दहेज-उरण-पनवेल-दाभोल पाइपलाइन नेटवर्क	935
7	दादरी-बवाना-नांगल पाइपलाइन नेटवर्क	868
8	दाभोल-बेंगलुरु पाइपलाइन नेटवर्क	1148
9	गुजरात क्षेत्रीय पाइपलाइन नेटवर्क	663
10	जगदीशपुर हल्दिया और बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन नेटवर्क	1098
11	केजी घाटी पाइपलाइन नेटवर्क	889
12	कोच्ची-कोट्टनाद-बेंगलुरु-मंगलुरु पाइपलाइन नेटवर्क	504
13	मुंबई क्षेत्रीय नेटवर्क	129
14	समर्पित नेटवर्क	233
	कुल लंबाई	13,389

टिप्पणियाँ :

काकिनाडा-भरूच पाइपलाइन 2019 में एक निजी कंपनी को दी गई थी और इस संपत्ति का संदर्भ मूल्यांकन लगभग 10 करोड रुपये प्रति कि.मी. था। अब, मुद्रीकरण के तहत, समान राशि को घटाकर 3 करोड़ रुपये प्रति कि.मी. कर दिया गया है। तो, यह राष्ट्रीय संपत्ति की एक बड़ी लूट होगी। यह नवउदारवादी शासन की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है जिसमें सार्वजनिक धन निजी कॉर्पोरेट को हस्तांतरित किया जाता है।

वास्तव में पाइपलाइन स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निवेश किया गया भारी धन कभी वापस नहीं आएगा। हालांकि नीति आयोग यह उल्लेख कर रहा है कि लेनदेन पीपीपी मॉडल पर होगा, लेकिन असलियत में पाइपलाइन का वास्तविक मालिक सीपीएसई केवल प्रायोजक के रूप में रह जाएगा। इसके अलावा, मुद्रीकरण परियोजना में टर्म रियायत है और पीएनजीआरबी (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड) समय-समय पर रियायत की राशि तय करेगा। इसलिए हमें नीति के पीछे छिपे एजेंडे को समझना चाहिए। पाइपलाइन के वास्तविक मूल्य को कम करके, पीएनजीआरबी द्वारा रियायत और टैरिफ निर्धारण की पेशकश करके, मोदी सरकार सीपीएसई की मूल्यवान गैस और उत्पाद पाइपलाइनों को निजी कंपनियों को सौंपने की कोशिश कर रही है।

पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षेत्र की संभावित परिसंपत्तियां:

वर्तमान में, पाइपलाइनों का संचालन सीपीएसई जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (गेल) द्वारा किया जाता है।

- भारत में एलपीजी और उत्पाद पाइपलाइनों की लंबाई 17,432 कि.मी. है।
- 43 उत्पाद पाइपलाइनों की कुल लंबाई 14063 कि.मी. है।
- कुल 06 एलपीजी पाइपलाइनों की लंबाई 3369 कि.मी. है।
- आईओसीएल 14,600 कि.मी. से अधिक लंबे कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और गैस पाइपलाइन के नेटवर्क का संचालन करता है जिसकी उत्पादन क्षमता 94.42 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) तेल और 21.69 एमएमएससीएमडी गैस है। उपयोग का स्तर 100% से अधिक है।

पाइपलाइन परिवहन का शुल्क कैसे निर्धारित किया जाता है:

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों (बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई पाइपलाइनों के अलावा) का टैरिफ पीएनजीआरबी (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ विनियमन, 2010) के तहत निर्धारित किया जाता है। तो, टैरिफ निर्धारण और राजस्व संग्रह केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। अब,

मुद्रीकरण प्रक्रियाओं में, सरकार निजी कंपनियों के लाभ के लिए प्रारंभिक चरण में टैरिफ कम कर सकती है। समय के साथ इसे भी समाप्त कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनी के पास सेवा शुल्क तय करने का अधिकार होगा। हम मुद्रीकरण प्रक्रिया से अधिक राजस्व संग्रह की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और राष्ट्र को राजस्व संग्रह के मामले में भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कॉर्पोरेट द्वारा इन परिसंपत्तियों से अर्जित राजस्व का एक छोटा हिस्सा सरकार के पास आएगा और सरकार एक कनिष्ठ भागीदार बनी रहेगी । दूसरी ओर, परिसंपत्ति मूल्यांकन तंत्र भी दोषपूर्ण है और अतिरिक्त रियायत के साथ घटी हुई दर तय की गई है। तो, यह स्पष्ट है कि, एक तरफ संपत्ति को निजी कॉरपोरेट को लंबी अवधि (30 साल से अधिक) के लिए बहुत कम मूल्य पर स्थानांतरित किया जाएगा और दूसरी ओर मुद्रीकरण से कम राजस्व आएगा। क्या इससे राष्ट्र के लिए कोई लाभ होगा ??

<u>हाइड्रोजन संयंत्र का मुद्रीकरण:</u>

मुद्रीकरण सूची में दो हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्रों को शामिल किया गया है। दोनों संयंत्र आईओसीएल की गुजरात रिफाइनरी से संबंधित हैं और इसका अनुमानित मुद्रीकरण मूल्य 1200 करोड़ रुपये है। सवाल यह है कि मुद्रीकरण प्रक्रिया में हाइड्रोजन संयंत्रों को क्यों शामिल किया जाता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन अगली पीढ़ी का ईंधन होगा और निकट भविष्य में हाइड्रोजन की मांग जबरदस्त होगी। हर देश में जीवाश्म ईंधन के बजाय हाइड्रोजन ईंधन उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी सरकार बार-बार हरित हाइड्रोजन उत्पादन की घोषणा कर रही है। हवाई रक्षा हथियारों में हाइड्रोजन का उपयोग और अंतरिक्ष वाहनों (क्रायोजेनिक) में भी ईंधन हाइड्रोजन पर निर्भर करता है। इसलिए, आने वाले दिनों में हाइड्रोजन के महत्व को जानते हुए, दो हाइड्रोजन संयंत्रों को मुद्रीकरण में शामिल किया गया है ताकि सरकार अपने कॉर्पोरेट साथियों को लाभ दे सके ।

गुजरात रिफाइनरी आईओसीएल द्वारा संचालित एक सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी है। रिफाइनरी के अंदर कोई निजी संस्था नहीं है और स्थायी कर्मचारी संयंत्रों का संचालन कर रहे हैं। हाइड्रोजन का उपयोग आमतौर पर डीजल और मिट्टी के तेल के उत्पादन के लिए रिफाइनरी हाइड्रोट्रीटर संयंत्रों में और पैराफिन वैक्स के उत्पादन के

लिए मोम हाइड्रो फिनिशिंग इकाई में किया जाता है। तो, यह रिफाइनरी के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक है। यदि हाइड्रोजन संयंत्रों का मुद्रीकरण किया जाता है, तो निम्नलिखित प्रभाव दिखाई देंगे-

- सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी में हाइड्रोजन संयंत्र निजी पार्टियों द्वारा संचालित किए जाएंगे।
- हाइड्रोजन का उत्पादन और आपूर्ति निजी पार्टियों पर निर्भर करेगी।
- कभी-कभी रिफाइनरी को हाइड्रोजन की कमी और अनियमित आपूर्ति का सामना करना पड़ेगा।
- हाइड्रोजन संयंत्रों के मुद्रीकरण के बाद, अन्य संयंत्रों को मुद्रीकरण के लिए रखा जाएगा और यह रिफाइनरियों के निजीकरण की प्रक्रिया होगी।
- हाइड्रोजन प्लांट से जुड़े स्थायी कर्मचारियों को जल्द ही हटा दिया जाएगा और उनके स्थान पर ठेका फिक्स टर्म के कर्मचारी लगाए जाएंगे।

<u>ईएसजी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण :</u>

पेट्रोलियम क्षेत्र में, ईएसजी (इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सल्फर रिकवरी यूनिट्स, और फ्लेयर गैस रिकवरी सिस्टम) को एनएमपी अवधि में मुद्रीकरण के लिए योजना बनाई गई है और उसका अनुमानित मूल्य 8000-10,000 करोड़ रुपये है। वर्तमान में, पीएसयू रिफाइनरीयों का संचालन करती हैं और स्पष्ट रूप से हर साल भारी धन प्राप्त होता है। सल्फर विभिन्न उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। सल्फर रिकवरी इकाइयों का मुद्रीकरण करने से, निजी पार्टियां भारी धन अर्जित करेंगे। प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली का प्रदूषण और आम जनता पर प्रभाव पड़ता है। उद्योग के करीब एफ्लुएंट सिस्टम में प्रदूषण को नियंत्रित नहीं करने के कई उदाहरण हैं। इसलिए, इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधि अगर सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों से हटाकर निजी मालिकों को दी जाती है, तो रिफाइनरियों की मुख्य गतिविधियों के कामकाज पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और समग्र रूप से समाज भी बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि यह आम तौर पर देखा गया है कि निजी उद्यमी प्रदूषण नियंत्रण में कभी सावधानी नहीं बरतते।

<u>वर्तमान टैरिफ और राजस्व अर्जन-बेमेल गणना:</u>

वर्तमान में, पीएसयू पीएनजीआरबी (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड) द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार सरकार को राजस्व का भुगतान कर रहे हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि इसे समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा और कंपनी के पास सेवा शुल्क तय करने का अधिकार होगा। एक बार संपत्ति के बंटवारे के बाद, शुल्कों में बढ़त की ओर संशोधन की पूरी संभावना है। इस मुद्रीकरण प्रक्रिया के माध्यम से एक कनिष्ठ भागीदार होने के नाते सरकार को एकत्रित कुल राजस्व के एक छोटे हिस्से से संतुष्ट रहना होगा। संपत्ति जो लंबी अवधि के लिए मुद्रीकरण के लिए रखी जाएगी, उसे निजी पार्टियों द्वारा हड़प लिया जाएगा। वर्तमान संपत्ति/परिसंपत्तियां, विशेष रूप से पाइपलाइन परिसंपत्तियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भूमि का अधिग्रहण करके कठिन क्षेत्रों में पाइपलाइन के निर्माण के भूमि मूल्य का भुगतान करके अर्जित की गई थी और उनका नियमित निगरानी और रखरखाव भी किया जाता है। पाइपलाइन का निर्माण एक बड़ा और कठिन काम है; यह किसी भूमि पर संयंत्र का निर्माण नहीं है। अब, मुद्रीकरण के माध्यम से, मोदी सरकार कॉरपोरेट के लाभ के लिए इन्हें निजी पार्टियों को सौंपने के लिए तैयार है। इसके परिणामस्वरूप, न केवल सार्वजनिक क्षेत्र इन सभी ढांचागत संपत्तियों को खो देंगे बल्कि एक बार फिर आम लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि पाइप्ड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी जिससे ईंधन के रूप में उपयोग करने वाले अंतिम उत्पादों में भी वृद्धि होगी।

<u>मुद्रीकरण के बाद संभावित समस्याएं/परिणाम :</u>

1) अब पीएसयू तेल कंपनियों की अपनी कच्चे तेल, गैस और उत्पाद पाइपलाइन हैं और वे आत्मनिर्भर हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार, वे पाइपलाइनों का उपयोग करते हैं और उसी के अनुसार योजना बनाई जाती है। अब पाइपलाइनों के मुद्रीकरण के बाद तेल कंपनियां निजी ऑपरेटरों पर निर्भर रहने के लिए बाध्य होंगी। कभी-कभी, निजी ऑपरेटर उत्पादों को समय पर पंप न करने से समस्या पैदा कर सकते हैं, जिससे रिफाइनरियों को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ सकती है। इस तरह, रिफाइनरियों का प्रदर्शन क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

2) वर्तमान में पाइपलाइन ड्यूटी में लगे अधिकारियों सहित स्थायी कर्मचारियों को मुद्रीकरण के बाद नौकरी छोड़नी होगी। निजी पार्टियां कभी भी अच्छा वेतन देकर इन कर्मचारियों को नहीं रखेगी। वे वर्तमान कर्मचारियों के बजाय ठेका/अनुबंध/फिक्स टर्म श्रमिकों को नियुक्त करेंगे। तो, स्थायी पदों की नौकरी छूट जाएगी। वर्तमान में आईओसीएल, एचपीसीएल और गेल के लगभग हजारों स्थायी कर्मचारी और अधिकारी पाइपलाइन ड्यूटी में कार्यरत हैं।

3) पीएनजीआरबी (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड) के मानदंडों के अनुसार राजस्व का भुगतान करने के बजाय, तेल सार्वजनिक उपक्रमों को अपने उत्पादों के परिवहन के लिए निजी पार्टियों को भारी पैसा देना होगा। इससे सार्वजनिक उपक्रमों के व्यय बजट में वृद्धि होगी।

4) सुरक्षा और अन्य मामले: पाइपलाइन सेवाओं में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मामला है। विभिन्न पेट्रोलियम पाइपलाइनों में आग और दुर्घटना के सैकड़ों उदाहरण हैं। पीएसयू तेल कंपनियां अपनी पाइपलाइन सेवाओं में मानक सुरक्षा उपायों को बनाए रखती हैं। मुद्रीकरण के बाद, हम पाइपलाइन संचालन में निजी पार्टियों से मानक सुरक्षा सावधानियों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। पाइपलाइन के रख-रखाव के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। अन्यथा, पूर्ण उपयोग संभव नहीं हो सकता। यह स्पष्ट नहीं है कि मुद्रीकरण के बाद पाइपलाइनों के नियमित रखरखाव के काम का खर्च कौन उठाएगा। नतीजतन, पाइपलाइनों का जीवन छोटा हो सकता है। अधिक पैसा कमाने के लिए निजी पक्ष उपरोक्त बातों का ध्यान नहीं रखेंगे।

<u>पेट्रोलियम क्षेत्र के कर्मचारियों के समक्ष अपील :</u>

बीपीसीएल को बेचने के फैसले के बाद अब मोदी सरकार पेट्रोलियम सेक्टर की कीमती और महत्वपूर्ण संपत्तियों को एनएमपी के नाम पर बेचने की तैयारी में है। यदि पाइपलाइनों का मुद्रीकरण किया जाता है, खुदरा दुकानों को निजी पार्टियों को दिया जाता है, तो तेल सार्वजनिक उपक्रमों के पास क्या बचेगा? यदि हाथ-पैर काट दिए जाएं,

तो मनुष्य कार्यहीन हो जाएगा। इसलिए, पेट्रोलियम क्षेत्र के श्रमिकों को हमारे देश में चल रहे निजीकरण विरोधी आंदोलन में भाग लेकर पीएसयू विरोधी और राष्ट्र विरोधी मुद्रीकरण पाइपलाइनों का विरोध करने के लिए आगे आना चाहिए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुद्रीकरण के अलावा, पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएनजीसी को बॉम्बे हाई की 60% गतिविधि विदेशी कंपनियों को सौंपने के लिए पत्र जारी किया। साथ ही रिफाइनरी सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत दी। सीमांत तेल क्षेत्र के बजाय अब प्रमुख तेल क्षेत्रों की नीलामी की जाएगी। बीपीसीएल के निजीकरण विरोधी आंदोलन को तेज करने की जरूरत है। पेट्रोलियम सेक्टर में चौतरफा हमला हो रहा है।

23 और 24 फरवरी 2022 को सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय संघों द्वारा बुलाई गई दो दिवसीय हड़ताल को सफल बनाया जाना चाहिए। सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को बचाने और राष्ट्र को बचाने और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के आक्रामक डिजाइन के खिलाफ निर्णायक और दृढ़ विरोध विकसित करने के लिए लड़ाई जारी रहनी चाहिए।

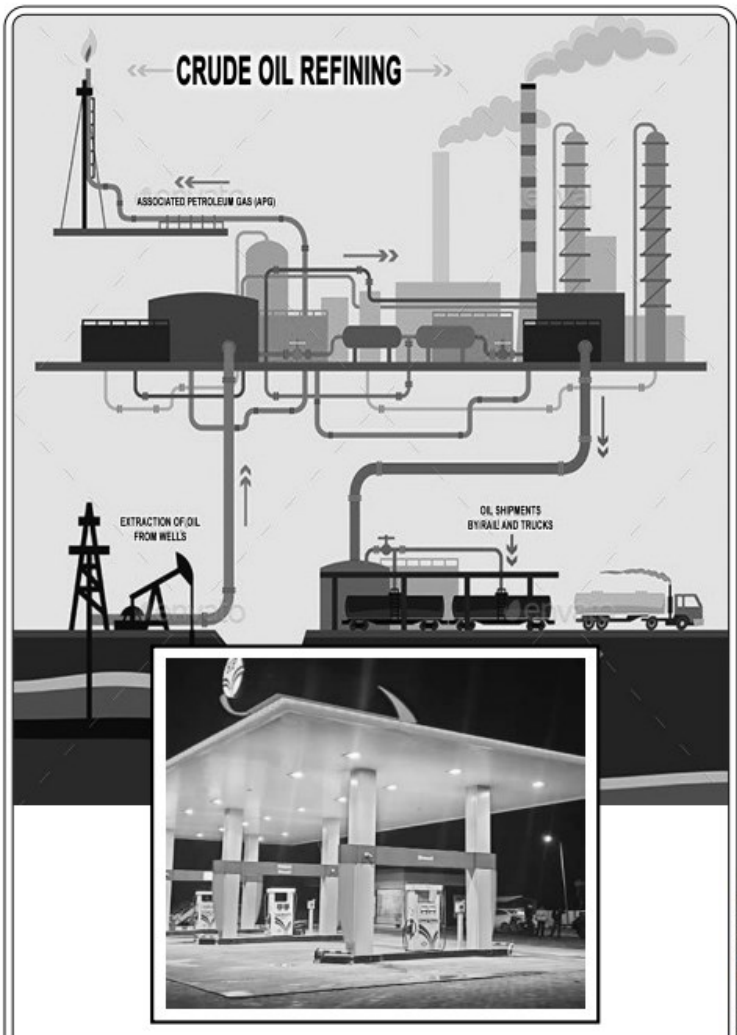

January 2022

Published by : NOGEN CHUTIA, General Secretary;
Petroleum and Gas Workers' Federation of India at Digboi, Assam, Pin Code-786171

Pajasakti Printers & Publishers Pvt.Ltd.@Vizag